नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 187
दि. 11.04.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

“भगवा लेकर आए हैं, भगवा पहनकर ही जाएंगे” बयान से गरमाई महाराष्ट्र की सियासत

‘ऑपरेशन टाइगर’ पर अरविंद सावंत का पलटवार, पाला बदल की अटकलें खारिज

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर तीखी बयानबाजी और सियासी अटकलों के केंद्र में आ गई है। इस बार चर्चा का कारण बना है कथित ‘ऑपरेशन टाइगर’, जिसे लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) के कई सांसदों को तोड़ने की रणनीति बनाई जा रही है। इन खबरों के बीच पार्टी के वरिष्ठ सांसद अरविंद सावंत ने सामने आकर न केवल इन दावों को खारिज किया, बल्कि बेहद सख्त और भावनात्मक अंदाज में अपनी निष्ठा भी दोहराई।

अरविंद सावंत ने कहा कि “हम भगवा लेकर आए हैं, भगवा पहनकर ही जाएंगे”, और यह बयान तेजी से महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल का केंद्र बन गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह किसी भी तरह के संपर्क या बैठक का हिस्सा नहीं रहे हैं और जो भी खबरें चल रही हैं, वे पूरी तरह अफवाह और राजनीतिक साजिश का हिस्सा हैं।

यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में एक कथित गुप्त बैठक की है, जिसमें उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस कथित रणनीति को ‘ऑपरेशन टाइगर’ नाम दिया गया, जिसका उद्देश्य आगामी चुनावों से पहले उद्धव गुट को कमजोर करना बताया जा रहा है।

रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि लोकसभा में उद्धव गुट के कुल 9 सांसदों में से 8 सांसदों ने शिंदे गुट के साथ किसी न किसी रूप में संपर्क किया है। जिन नामों की चर्चा मीडिया में सामने आई, उनमें अरविंद सावंत, संजय पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल, राजाराम वाकचौरे, संजय जाधव, ओम राजे निंबालकर और राजाभाऊ वाजे जैसे नेता शामिल बताए गए। कहा गया कि इनमें से कुछ सांसद व्यक्तिगत रूप से बैठक में शामिल हुए, जबकि कुछ

ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे।

इन दावों के सामने आते ही महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई और दोनों गुटों के बीच बयानबाजी शुरू हो गई। हालांकि, अरविंद सावंत ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन सभी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया।

सावंत ने कहा कि वह 1968 से शिवसेना से जुड़े हुए हैं और उनका राजनीतिक जीवन पूरी तरह पार्टी की विचारधारा और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के प्रति समर्पित रहा है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 2019 में उन्होंने केंद्रीय मंत्री का पद छोड़कर भी पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा साबित की थी। उनके अनुसार, ऐसे में उनके खिलाफ पाला बदलने की अफवाहें पूरी तरह निराधार हैं और राजनीतिक लाभ के लिए फैलाई जा रही हैं।

उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में संसद भवन में शिवसेना (UBT) के नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ था, जिसमें पार्टी के सभी सांसद मौजूद थे। उनके अनुसार, जब सभी सांसद एकजुट हैं और पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं, तब इस तरह की “गुप्त बैठकों” की खबरें केवल भ्रम फैलाने के लिए बनाई जा रही हैं।

इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना (UBT) के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है और इस तरह की खबरों का उद्देश्य विपक्ष को कमजोर दिखाना है। राउत ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी खेमे द्वारा मीडिया के माध्यम से “ऑपरेशन” जैसी कहानियां गढ़ी जा रही हैं, ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके।

वहीं, शिंदे गुट के नेताओं ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। प्रताप सरनाईक ने दावा किया कि उद्धव ठाकरे गुट के भीतर असंतोष और अस्थिरता का माहौल है, जिसके कारण इस तरह की चर्चाएं लगातार सामने आती रहती हैं। हालांकि, उन्होंने सीधे किसी बैठक या ऑपरेशन की पुष्टि नहीं की।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महाराष्ट्र में आगामी चुनावों को देखते हुए दोनों ही गुट अपनी-अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हैं। शिवसेना का विभाजन पहले ही राज्य की राजनीति को दो धड़ों में बांट चुका है, और अब दोनों पक्ष एक-दूसरे पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं।

‘ऑपरेशन टाइगर’ जैसी खबरें भले ही आधिकारिक रूप से पुष्ट न हों, लेकिन यह जरूर संकेत देती हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब भी अस्थिरता और रणनीतिक हलचल जारी है। ऐसे समय में नेताओं के बयान और पलटवार न केवल राजनीतिक संदेश देते हैं, बल्कि कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी सीधा असर डालते हैं।

अरविंद सावंत के बयान ने शिवसेना (UBT) खेमे में जहां एक तरह से एकजुटता का संदेश दिया है, वहीं दूसरी ओर विरोधी गुटों को यह संदेश देने की कोशिश भी की है कि पार्टी में टूट-फूट की अटकलें वास्तविकता से दूर हैं।

फिलहाल, इस पूरे विवाद पर आधिकारिक पुष्टि का अभाव है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर जारी है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह केवल मीडिया अटकलें थीं या फिर इसके पीछे कोई वास्तविक राजनीतिक रणनीति भी मौजूद है।

महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है, जहां बयान, अफवाहें और रणनीतियां मिलकर भविष्य की दिशा तय कर रही हैं।

बेमौसमी बारिश से देशभर में 2.49 लाख हेक्टेयर रबी फसलें प्रभावित

गेहूं को सबसे ज्यादा नुकसान; केंद्र ने राहत का भरोसा दिया

भोपाल। देश के कई राज्यों में हाल ही में हुई बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने रबी सीजन की फसलों पर गंभीर असर डाला है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को जानकारी दी कि अब तक करीब 2.49 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी फसलें प्रभावित हुई हैं। इनमें सबसे अधिक नुकसान गेहूं की फसल को हुआ है, जबकि आम और लीची जैसी बागवानी फसलें भी बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई हैं।

यह बयान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आयोजित ‘उन्नत कृषि मेला’ के उद्घाटन अवसर पर दिया गया, जहां कृषि मंत्री ने किसानों से सीधे संवाद किया और उन्हें आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार इस संकट की घड़ी में पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि फसलों के नुकसान का आकलन तेजी से किया जा रहा है और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आगे की राहत और मुआवजे की प्रक्रिया तय की जाएगी।

कृषि मंत्री ने बताया कि स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन करने के लिए तीन विभागों की संयुक्त टीमें प्रभावित इलाकों में सर्वे कर रही हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट 8 अप्रैल तक की घटनाओं के आधार पर तैयार की गई है, जिसमें स्पष्ट हुआ है कि गेहूं के अलावा बागवानी फसलों को भी काफी नुकसान

पहुंचा है। विशेष रूप से आम और लीची की पैदावार पर मौसम की मार भारी पड़ी है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान की आशंका बढ़ गई है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, 2 से 8 अप्रैल के बीच देश के कई हिस्सों में असामान्य मौसम पैटर्न देखा गया। पूर्वोत्तर, मध्य, दक्षिण और उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों में भारी बारिश दर्ज की गई। इस दौरान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों में ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने स्थिति को और गंभीर बना दिया।

इन मौसमी घटनाओं के कारण खेतों में खड़ी फसलें बुरी तरह प्रभावित हुईं। कई स्थानों पर कटाई के लिए तैयार गेहूं की फसल गिर गई, जिससे उत्पादन पर सीधा असर पड़ने की संभावना है। किसानों का कहना है कि यह समय उनकी सालभर की मेहनत का होता है और अचानक हुए इस मौसम बदलाव ने उनकी आर्थिक स्थिति को गहरा झटका दिया है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रभावित क्षेत्र में सबसे बड़ा हिस्सा गेहूं का है, जो रबी सीजन की प्रमुख फसल मानी जाती है। इसके अलावा सरसों, चना और अन्य दलहनी फसलें भी आंशिक रूप से प्रभावित हुई हैं। कृषि विभाग के अधिकारी लगातार फील्ड विजिट कर रहे हैं ताकि नुकसान का सटीक आकलन किया जा सके।

कृषि मंत्री ने भरोसा दिलाया कि जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर जल्द ही राहत पैकेज की घोषणा की जा सकती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए कृषि बीमा योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचना जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि बदलते जलवायु पैटर्न के कारण इस तरह की बेमौसमी घटनाएं अब अधिक सामान्य होती जा रही हैं, जिससे कृषि क्षेत्र पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में फसल सुरक्षा, आधुनिक तकनीक और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत करना समय की आवश्यकता बन गया है।

फिलहाल सरकार की प्राथमिकता प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से सर्वे पूरा कराकर वास्तविक नुकसान का आंकलन करना और किसानों को समय पर राहत पहुंचाना है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति को और अधिक बिगड़ने से बचाया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत जनगणना रोकने की याचिका खारिज की, भाषा पर जताई सख्त नाराजगी; केंद्र को बड़ी राहत

नई दिल्ली। देश में प्रस्तावित जातिगत जनगणना को रोकने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। इस अहम फैसले के साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में इस्तेमाल की गई भाषा पर कड़ी नाराजगी जताई और इसे न्यायिक प्रक्रिया की मर्यादा के खिलाफ बताया। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ कहा कि अदालत का उपयोग गंभीर और जिम्मेदार मुद्दों के लिए होना चाहिए, न कि असंयमित और आपत्तिजनक शब्दों के लिए।

इस पीठ में न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली भी शामिल थे। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने याचिकाकर्ता से सीधे और सख्त लहजे में सवाल किया कि याचिका में इस तरह की भाषा किसने लिखी और इसका आधार क्या है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जनहित याचिका का उद्देश्य न्यायिक समाधान होना चाहिए, न कि भावनात्मक या भड़काऊ भाषा के जरिए मुद्दे को प्रस्तुत करना।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी प्रकार की ऐसी याचिका पर विचार नहीं करेगा जो न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करती हो या जिसमें अनावश्यक रूप से तीखे और अनुचित शब्दों का प्रयोग किया गया हो। इसके साथ ही अदालत ने जातिगत जनगणना पर रोक लगाने की मांग को अस्वीकार करते हुए याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया।

याचिका में केंद्र सरकार से यह भी अनुरोध किया गया था कि देश में एकल संतान वाले परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने के लिए विशेष नीति बनाई जाए। हालांकि, अदालत ने इस मांग को भी याचिका के दायरे से बाहर बताते हुए कोई राहत देने से इनकार कर दिया।

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत जनगणना से जुड़े मामलों पर दखल देने से इनकार किया हो। इससे पहले फरवरी में भी एक अन्य जनहित याचिका पर सुनवाई से अदालत ने मना कर दिया था, जिसमें 2027 की जनगणना प्रक्रिया में जाति आधारित आंकड़ों के संग्रह और सत्यापन पर सवाल उठाए गए थे।

देश में प्रस्तावित 2027 की राष्ट्रीय जनगणना को लेकर पहले से ही व्यापक चर्चा चल रही है। यह स्वतंत्र भारत की 16वीं जनगणना होगी और इसके साथ कई ऐतिहासिक बदलाव भी जुड़े हैं। पहली बार इस जनगणना को पूरी तरह डिजिटल तरीके से संचालित किए जाने की तैयारी है, जिससे डेटा संग्रह, सत्यापन और प्रोसेसिंग अधिक तेज और सटीक हो सके।

इसके अलावा यह भी संभावना है कि इस बार जनगणना में जाति आधारित आंकड़ों को शामिल किया जाए, जिसे लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर लंबे समय से बहस जारी है। कई दल और सामाजिक संगठन इसे सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक बता रहे हैं, जबकि कुछ वर्गों का मानना है कि इससे सामाजिक विभाजन और गहरा हो सकता है।

सरकार की ओर से पहले ही संकेत दिए जा चुके हैं कि जनगणना प्रक्रिया को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाएगा और डेटा संग्रह को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। डिजिटल जनगणना के माध्यम से न केवल जनसंख्या का सटीक आकलन किया जाएगा, बल्कि सामाजिक-आर्थिक नीतियों के निर्माण में भी इसे आधार बनाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को केंद्र सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी राहत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे जातिगत जनगणना की प्रक्रिया पर फिलहाल किसी तरह की न्यायिक बाधा नहीं रही है। अब सरकार अपनी निर्धारित योजना के अनुसार जनगणना की तैयारियों को आगे बढ़ा सकेगी। अदालत ने सुनवाई के दौरान यह भी संकेत दिया कि न्यायालय में दाखिल याचिकाओं को गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ तैयार किया जाना चाहिए। किसी भी तरह की गैर-जिम्मेदार भाषा न केवल मामले की गंभीरता को प्रभावित करती है, बल्कि न्यायालय के समय और संसाधनों की भी अनावश्यक बर्बादी करती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह रुख भविष्य में जनहित याचिकाओं की गुणवत्ता को भी प्रभावित करेगा और याचिकाकर्ताओं को अधिक सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करेगा। अदालत की सख्त टिप्पणी से यह भी स्पष्ट संदेश गया है कि संवैधानिक मामलों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग भी मर्यादा के दायरे में होना चाहिए।

जातिगत जनगणना का मुद्दा भारत में लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का हिस्सा रहा है। 1931 के बाद यह पहली बार होगा जब देश में व्यापक स्तर पर जातिगत आंकड़ों को शामिल करने की बात सामने आई है। यदि यह लागू होता है तो यह नीति निर्माण, आरक्षण व्यवस्था और सामाजिक योजनाओं पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।

वर्तमान में सरकार का फोकस जनगणना को डिजिटल और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने पर है, ताकि देश की वास्तविक जनसंख्या संरचना का अधिक सटीक चित्र सामने आ सके। इसके जरिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं को अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा।

संयुक्त राष्ट्र CESCR में प्रीति सरन का पुनर्निर्वाचन, तीन साल के नए कार्यकाल से भारत की वैश्विक भूमिका को मिला नया आयाम

नई दिल्ली। वरिष्ठ भारतीय राजनयिक प्रीति सरन को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से जुड़ी प्रमुख समिति CESCR (Committee on Economic, Social and Cultural Rights) में एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें 2027 से शुरू होने वाले तीन वर्ष के नए कार्यकाल के लिए पुनः चुना गया है। इस निर्णय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती कूटनीतिक स्वीकार्यता और वैश्विक मानवाधिकार मंचों पर उसकी मजबूत उपस्थिति के रूप में देखा जा रहा है।

वर्तमान में CESCR की अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहीं प्रीति सरन का दोबारा चयन इस बात का संकेत है कि समिति के सदस्य देशों ने उनके नेतृत्व, अनुभव और कार्यशैली पर पूरा भरोसा जताया है। संयुक्त राष्ट्र के भीतर यह समिति उन प्रमुख निकायों में शामिल है, जो सदस्य देशों द्वारा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय संधियों के अनुपालन की निगरानी करती है।

CESCR संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें 18 स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इन विशेषज्ञों का कार्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सदस्य देश अपने नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और न्यायसंगत कार्य स्थितियों जैसे मौलिक अधिकार उपलब्ध कराने में अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करें। इस लिहाज से यह समिति वैश्विक नीति निर्माण और मानवाधिकार संरक्षण की दिशा में एक निर्णायक भूमिका निभाती है।

प्रीति सरन का पुनर्निर्वाचन ऐसे समय में हुआ है जब दुनिया भर में सामाजिक-आर्थिक असमानता, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, रोजगार संकट और मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दे लगातार चर्चा में हैं। ऐसे परिदृश्य में उनका नेतृत्व CESCR की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके चयन के बाद अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक हलकों में यह भी चर्चा तेज हो गई है कि भारत की भागीदारी वैश्विक संस्थाओं में केवल औपचारिक नहीं रह गई है, बल्कि अब नीति-निर्माण और निगरानी प्रक्रियाओं में भी प्रभावशाली होती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रीति सरन जैसे अनुभवी राजनयिकों की मौजूदगी भारत की छवि को एक जिम्मेदार और सक्रिय वैश्विक शक्ति के रूप में और मजबूत करती है।

प्रीति सरन का राजनयिक करियर लगभग 36 वर्षों से अधिक का रहा है, जिसमें उन्होंने भारतीय विदेश सेवा (IFS) के तहत कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में भारत के विभिन्न राजनयिक मिशनों का नेतृत्व किया और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई।

विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने दक्षिण-पूर्व एशिया, कनाडा और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों के साथ भारत के संबंधों को नई दिशा दी। उनकी नीतिगत समझ और रणनीतिक दृष्टिकोण ने भारत की विदेश नीति को कई स्तरों पर मजबूती प्रदान की।

वियतनाम में भारत की राजदूत और टोरंटो में महावाणिज्यदूत के रूप में उनकी सेवाओं को विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है। इन जिम्मेदारियों के दौरान उन्होंने व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाई।

CESCR में उनके नेतृत्व को लेकर यह भी माना जाता है कि उन्होंने समिति की कार्यप्रणाली को अधिक समावेशी और परिणामोन्मुख बनाने पर जोर दिया है। उनके कार्यकाल में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों को अधिक व्यापक दृष्टिकोण से देखने की प्रवृत्ति विकसित हुई है, जिससे वैश्विक स्तर पर नीति निर्माण में अधिक संतुलन आया है।

उनके पुनर्निर्वाचन को संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में भारत के बढ़ते प्रभाव के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारत की उस कूटनीतिक क्षमता को दर्शाता है, जो अब वैश्विक संस्थानों में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की ओर अग्रसर है।

आने वाले तीन वर्षों में CESCR के सामने कई गंभीर चुनौतियाँ रहेंगी, जिनमें वैश्विक आर्थिक असमानता, जलवायु परिवर्तन के सामाजिक प्रभाव, स्वास्थ्य सेवाओं तक असमान पहुंच और श्रम अधिकारों की सुरक्षा जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। ऐसे में प्रीति सरन की भूमिका इन चुनौतियों के समाधान में अहम साबित हो सकती है।

संयुक्त राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण निकाय में उनकी पुनः नियुक्ति न केवल भारत के लिए गर्व का विषय है, बल्कि यह वैश्विक मानवाधिकार संरचना में भारतीय विशेषज्ञता की बढ़ती स्वीकार्यता का भी प्रतीक है।

संपादकीय

आक्रामकता पर अंकुश लगाने की पहल हो

बदलते वक्त के साथ समाज में बढ़ते आक्रामक व्यवहार के चलते अपराधों का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन किशोरों की अपराधों में संलिप्तता बढ़ना गंभीर चिंता का विषय है। हाल के दिनों में देश में किशोर अपराधों से जुड़ी अनेक ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिन्होंने देश को गहरी चिंता में डाला है। जो बाल अपराधों के सामाजिक कारणों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत पर बल देता है। निस्संदेह, यह विचारणीय प्रश्न है कि छोटे-छोटे विवादों के बीच किशोर हिंसक क्यों हो रहे हैं। जिसकी परिणति अकसर क्रूर हत्या के रूप में सामने आती है। पिछले दिनों दिल्ली के दयालपुर क्षेत्र में सिर्फ चार सौ रुपये के विवाद में एक युवक की निर्मम हत्या डराने वाली है। वहीं किशोरों में कानून का भय न होना गंभीर मसला है। बताया जाता है कि इस युवक की हत्या में तीन नाबालिग संलिप्त थे। इस घटना में तीन किशोर एक युवक पर लगातार चाकू मारते रहे। हिंसक प्रवृत्ति की पराकाष्ठा देखिए कि इनका चौथा साथी बाकायदा मोबाइल पर घटना का वीडियो बनाता रहा। निस्संदेह, यह घटना किसी भी सभ्य समाज में सिहरन पैदा करने वाली है कि किशोर में यह आपराधिक दुस्साहस कहां से आ रहा है। जाहिर बात है कि इन किशोरों में पुलिस-प्रशासन का कोई भय नहीं था, तभी वे सरेआम चाकूबाजी करते रहे। देश की राष्ट्रीय राजधानी जहां के बारे में अकसर कहा जाता है कि पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाने में अग्रणी रहता है, वहां यह घटना सामने आयी। सवाल उठाया जा सकता है कि देश के दूर-दराज के इलाकों में यह स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि किशोरों की आपराधिक घटनाओं में तेजी से बढ़ती भूमिका की असली वजह क्या है? उल्लेखनीय है कि दयालपुर की घटना से पहले भी कई गंभीर अपराधों में किशोरों की संलिप्तता की घटनाएं गाहे-बगाहे सामने आती रही हैं। लेकिन किशोर अपराध से जुड़े कानून उन्हें जल्दी रिहा करा देते हैं।

दरअसल, देश में अकसर किशोरों के गंभीर अपराधों में लिप्त होने के चलते उनकी वयस्क होने की उम्र घटाने की मांग होती है। इसकी वजह यह है कि किशोर गंभीर अपराधों में संलिप्तता के बावजूद किशोर अपराध से जुड़े कानूनों के लचीलेपन के चलते जेल से जल्दी रिहा हो जाते हैं। जेल से बाहर आने के बाद फिर दूसरे गंभीर अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। यह गंभीर मुद्दा है जिसके समाधान को केंद्र सरकार को अपनी प्राथमिकता बनाना चाहिए। दरअसल, इंटरनेट के तेजी से प्रसार और सोशल मीडिया में अपराधों से जुड़ी घातक सामग्री की उपलब्धता किशोरों में भटकाव को बढ़ावा दे रही है। हिंसक फिल्में और अन्य माध्यमों में अपराध के तौर-तरीके से जुड़ी सामग्री किशोर मन पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। देश में संयुक्त परिवारों के बिखराव व बच्चों पर मां-बाप का नियंत्रण कम होने से कई किशोर बुरी संगति के चलते अपराधजगत की फिसलन में उतर जाते हैं। दूसरी ओर स्कूल-कालेजों में शिक्षकों की वह भूमिका नहीं रही, जो सख्ती से किशोरों के व्यवहार को नियंत्रित कर सके। आज उनकी सोच को मोबाइल व सोशल मीडिया पर प्रसारित विकृत सूचनाएं प्रभावित कर रही हैं। समाज के व्यवहार में एक किस्म की आक्रामकता नजर आती है। वहीं दूसरी ओर आपराधिक गिरोह व गैंग भी अपने आपराधिक कृत्यों को अंजाम देने कि लिए किशोरों का इस्तेमाल करते हैं। सवाल यह भी है कि किशोरों तक घातक हथियार कहां से और कैसे पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, नशे की दलदल में फंसने वाले किशोर भी कालांतर नशा खरीदने के लिये पैसे जुटाने के लिये अपराध की गली में उतर जाते हैं। फिर गंभीर अपराधों को अंजाम देने लगते हैं। निश्चित रूप से बदलते वक्त के साथ पुलिस की भूमिका व कार्यशैली में बदलाव लाने की जरूरत है। साथ ही समाज में भी जागरूकता लानी आवश्यक है ताकि किशोरों को अपराध की राह पर बढ़ने से रोका जा सके। सरकार और समाज के साझे प्रयासों से ही इस संकट से उबरने में मदद मिल सकती है।

पानी आपूर्ति की निरंतरता व शुद्धता जरूरी

“ बजट में जल सुविधा विस्तार के लिए सरकार ने बड़ी राशि का प्रावधान किया है लेकिन जब तक सरकार ‘नल’ लगाने की संख्या की होड़ छोड़कर ‘जल’ की गुणवत्ता, वर्षा जल संचयन और जवाबदेह प्रबंधन पर ध्यान नहीं देगी, तब तक बजट की घोषणाएं सार्थक न होंगी।

भारत दुनिया की लगभग 18 प्रतिशत आबादी का घर है, लेकिन हमारे पास वैश्विक मीठे पानी के संसाधनों का केवल 4 प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है। यह असंतुलन ही देश में जल संकट की बुनियादी जड़ है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्टों के अनुसार, लगभग 60 करोड़ भारतीय उच्च से अत्यधिक जल तनाव का सामना कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हम अपने नागरिकों को एक गिलास शुद्ध पानी देने में सक्षम हैं?

इस साल के फरवरी 2026 में पेश किए गए केंद्रीय बजट में जल शक्ति मंत्रालय के लिए 67,600 करोड़ रुपये का आवंटन कर सरकार ने अपनी मंशा तो साफ कर दी है। लेकिन जल जीवन मिशन और ‘अमृत’ जैसे प्रोजेक्ट्स के पिछले सात वर्षों के सफर को देखें, तो यह स्पष्ट होता है कि व्यवस्था ने केवल पाइप बिछाने की गति को ही सफलता मान लिया, जबकि पानी की शुद्धता और उसकी निरंतरता को हाशिए पर धकेल दिया गया।

भारत के शहरी-ग्रामीण इलाकों में दूषित पानी को लेकर बात करें तो दिसंबर, 2025 से जनवरी 2026 के पहले सप्ताह के बीच ही देश के 26 प्रमुख शहरों में सीवेज मिश्रित पानी पीने से 5,500 से अधिक लोग बीमार हुए और कम से कम 34 लोगों की मौत दर्ज की गई। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दिसंबर, 2025 के अंतिम सप्ताह में पाइपलाइन में सीवेज का पानी मिलने से 37 लोगों की मौत हो गई और 1,400 से अधिक लोग अस्पताल पहुंच गए। इसी तरह, जनवरी, 2026 की शुरुआत में बेंगलुरु के पॉश इलाकों और गांधीनगर (गुजरात) में सैकड़ों बच्चे दूषित पानी के कारण टाइफाइड और डायरिया का शिकार हुए। अगस्त, 2019 में जब ‘जल जीवन मिशन’ शुरू हुआ, तब लक्ष्य था 2024 तक हर घर को नल से जोड़ना। सरकारी पोर्टल के अनुसार, जनवरी 2026 तक देश के लगभग 15.8 करोड़ घरों में नल लग चुके हैं। लेकिन इस ‘संख्यात्मक सफलता’ के पीछे एक बड़ा ढांचागत दोष है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 79वें दौर के आंकड़ों के अनुसार, पाइपलाइन कवरेज के बावजूद केवल 39 प्रतिशत ग्रामीण घर ही नल के पानी को अपने प्राथमिक स्रोत के रूप में उपयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में यह उपयोग दर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच है।

देखा गया कि हजारों गांवों में पाइप और नल तो लगे हैं, लेकिन पानी का दबाव इतना कम है कि वह अंतिम घर तक नहीं पहुंचता। कई स्थानों पर तो नल केवल ‘शोपीस’ बनकर रह गए हैं। फिर नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के 60 प्रतिशत जल स्रोत सूख चुके हैं। मैदानी इलाकों में भूजल का स्तर इतनी तेजी से गिर रहा है कि नलों के लिए पानी का कोई स्थायी स्रोत ही नहीं बचा है। जवाबदेही की कमी के कारण पाइपलाइनें बिछाने के कुछ महीनों बाद ही फटने लगी हैं।

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में भूजल का स्तर काफी नीचे गिर गया है। कृषि में ‘वाटर गज़लर’ फसलों (जैसे धान और गन्ना) के लिए अंधाधुंध पंपिंग ने जलभृतों (एक्वाफर्स) को सुखा दिया है। इन सभी कारणों से पानी की गुणवत्ता में भी गिरावट आ रही है। बड़ी मात्रा में सतही जल प्रदूषित है। भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम की बढ़ती मात्रा ‘कैंसर बेल्ट’ जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे रही है।

गांवों से पलायन और शहरों का अनियोजित विकास, सरकार द्वारा तैयार मूलभूत संरचना पर आवश्यकता से अधिक बोझ ने महानगरों को पानी के लिए कंगाल बना दिया है। दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे महानगरों में पाइपलाइन लीकेज और सीवेज मिक्सिंग एक आम समस्या बन गई है।

सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना ‘अमृत 2.0’ का लक्ष्य शहरों को ‘वॉटर सिक्योर’ बनाना था। लेकिन संसदीय स्थायी समिति की दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, शहरी भारत में अभी भी बड़ी मात्रा में पानी ‘नॉन-रेवेन्यू वॉटर’ के रूप में बर्बाद हो जाता है, जो मुख्य रूप से पाइपलाइनों के रिसाव के कारण होता है। सबसे बड़ी विफलता जल वितरण और सीवेज प्रबंधन के बीच समन्वय का अभाव है।

बजट 2026 में सरकार ने जल जीवन मिशन की समय सीमा को बढ़ाकर दिसंबर 2028 कर दिया है। यह एक मूक स्वीकारोक्ति है कि 2024 और 2025 के लक्ष्य पूरे नहीं हो सके। बजट में इस बार ‘वेस्ट वॉटर रिसाइकिलिंग’ और ‘यूज्ड वॉटर ट्रीटमेंट’ पर जोर दिया गया है, लेकिन इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल शहरी निकायों के पास नहीं है। पिछले वित्त वर्ष में जल शक्ति मंत्रालय ने आवंटित बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं किया, जो प्रशासनिक कमजोरी को दर्शाता है।

बजट 2026 में राज्यों के लिए 67,600 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग तभी सार्थक होगा जब उसे ‘क्वालिटी ऑडिट’ से जोड़ा जाए। आज भी देश के 230 जिलों में आर्सेनिक और 469 जिलों में फ्लोराइड पानी में घुला हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े चेतावनी देते हैं कि असुरक्षित पानी से भारत में होने वाली मौतें तेजी से बढ़ सकती हैं। बजट के आंकड़ों और धरातल की हकीकत के बीच जो गहरी खाई बन गई है, उसे भरने के लिए केवल धन की नहीं बल्कि एक ईमानदार और दीर्घकालिक विज़न की आवश्यकता है।

बजट में जल सुविधा के लिए सरकार ने बड़ी राशि का प्रावधान किया है लेकिन जब तक सरकार ‘नल’ लगाने की संख्या की होड़ छोड़कर ‘जल’ की गुणवत्ता, वर्षा जल संचयन और जवाबदेह प्रबंधन पर ध्यान नहीं देगी, तब तक बजट की घोषणाएं सार्थक न होंगी।

प्रेरणा

जन्मभूमि की अनमोल महिमा और उसकी सुगंध का आध्यात्मिक सत्य

जब भगवान श्रीराम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे लंका जाकर विभीषण का राजतिलक संपन्न कराएं, तब यह केवल एक राजनीतिक कर्तव्य नहीं था, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक सीख का आरंभ भी था। लक्ष्मण जब लंका पहुंचे, तो उन्होंने उस स्वर्णमयी नगरी की भव्यता को देखा—हर ओर सोने की चमक, सुसज्जित महल, और सुव्यवस्थित उद्यान। लंका केवल एक राज्य नहीं थी, बल्कि वैभव और समृद्धि का अद्भुत उदाहरण थी। वहां की वाटिकाओं में खिले हुए रंग-बिरंगे पुष्प, जिनकी सुगंध वातावरण को मधुर बना रही थी, लक्ष्मण के मन को मोह लेने के लिए पर्याप्त थे।

लक्ष्मण, जो स्वयं एक तपस्वी और त्यागी स्वभाव के थे, इस भौतिक सौंदर्य को देखकर कुछ क्षणों के लिए आकर्षित हो गए। उन्होंने उन पुष्पों को निहारा, उनकी सुगंध को अनुभव किया, और मन ही मन यह विचार किया कि यदि कुछ समय इस अद्भुत नगरी में बिताया जाए तो कितना सुखद होगा। यह एक स्वाभाविक मानवीय भावना थी—जहां सौंदर्य और सुविधा हो, वहां मन आकर्षित होना ही है।

विभीषण का विधिपूर्वक राजतिलक संपन्न कराने के बाद जब लक्ष्मण वापस श्रीराम के पास लौटे, तो उनके मन में लंका के प्रति एक हल्का आकर्षण बना हुआ था। उन्होंने श्रीराम के चरणों की सेवा करते हुए विनम्रता से कहा कि लंका अत्यंत सुंदर और दिव्य नगरी है, और यदि आज्ञा हो तो वे कुछ समय वहां निवास करना चाहेंगे। यह सुनकर श्रीराम मुस्कुराए, क्योंकि वे लक्ष्मण के मन के भाव को भलीभांति समझ रहे थे। श्रीराम ने लक्ष्मण को जो उत्तर दिया, वह केवल एक भाई का उपदेश नहीं था, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक गहन जीवन-दर्शन था। उन्होंने कहा कि यह सत्य है कि लंका स्वर्ग के समान सुंदर और आकर्षक है, किंतु अपनी जन्मभूमि अयोध्या की तुलना उससे नहीं की जा सकती। उन्होंने समझाया कि जहां मनुष्य का जन्म होता है, उस भूमि की मिट्टी में एक विशेष सुगंध होती है, जो किसी भी अन्य स्थान में नहीं मिल सकती।

यह सुगंध केवल भौतिक नहीं होती, बल्कि उसमें भावनाओं, स्मृतियों, संस्कारों और आत्मिक जुड़ाव की गहराई समाहित होती है। जन्मभूमि केवल एक स्थान नहीं होती, बल्कि वह हमारे अस्तित्व का आधार होती है। वहीं हमने पहला कदम रखा, वहीं हमारे संस्कारों का निर्माण हुआ, और वहीं हमारे जीवन की नींव पड़ी। लक्ष्मण ने जब श्रीराम के इन शब्दों को सुना, तो उनका मन तुरंत परिवर्तित हो गया। उन्हें यह अनुभूति हुई कि बाहरी वैभव और आकर्षण क्षणिक होते हैं, जबकि जन्मभूमि का महत्व शाश्वत होता है। उन्होंने स्वीकार किया कि अयोध्या वास्तव में तीनों लोकों से न्यारी है, क्योंकि वहां केवल भौतिक सुंदरता ही नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और अपनेपन का अनुभव भी मिलता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे संसार में कितनी ही भव्य और आकर्षक जगहें क्यों न हों, अपनी जन्मभूमि का स्थान सर्वोपरि होता है। आज के आधुनिक युग में, जब लोग बेहतर अवसरों की तलाश में अपने देश और शहर को छोड़कर विदेशों में बस जाते हैं, तब भी उनके मन के किसी कोने में अपने गांव, अपने शहर, और अपनी मातृभूमि के प्रति एक गहरा लगाव बना रहता है। जन्मभूमि की सुगंध एक ऐसी अनुभूति है, जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह उस मिट्टी की खुशबू है, जिसमें हमारे बचपन की यादें बसी होती हैं। यह उस हवा की ताजगी है, जिसमें हमारे पहले सपने उड़े होते हैं। यह उस जल की शीतलता है, जिसने हमारे जीवन को पोषित किया होता है।

जब कोई व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से दूर होता है, तब उसे उस भूमि का महत्व और भी अधिक समझ में आता है। वह वहां की छोटी-छोटी बातों को याद करता है—गली-कूचों की हलचल, त्योहारों की रौनक, और अपने लोगों का स्नेह। ये सभी चीजें मिलकर एक ऐसी भावना का निर्माण करती हैं, जिसे कोई भी भौतिक संपदा प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। श्रीराम का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी जन्मभूमि का सम्मान करना चाहिए, उसके प्रति गर्व महसूस करना चाहिए, और उसके विकास के लिए योगदान देना चाहिए। क्योंकि अंततः वही भूमि हमें हमारी पहचान देती है, हमें हमारे मूल से जोड़ती है, और हमें यह एहसास कराती है कि हम कौन हैं। इस प्रकार, लक्ष्मण का लंका के प्रति आकर्षण और श्रीराम द्वारा दिया गया उपदेश हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य सिखाता है—कि बाहरी आकर्षण चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, अपनी जन्मभूमि की महत्ता उससे कहीं अधिक होती है। उसकी सुगंध, उसका अपनापन, और उसका आत्मिक संबंध हमें जीवन भर एक अदृश्य डोर से बांधे रखता है।

तीन राज्यों में बंपर वोटिंग ने क्या संदेश दिया? क्या जनादेश अभी से साफ नजर आ रहा है?

असम, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों में इस बार जबरदस्त मतदान ने लोकतंत्र की मजबूती का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। लगभग 80 प्रतिशत के औसत मतदान ने यह संकेत दिया है कि जनता न केवल राजनीतिक रूप से जागरूक है, बल्कि अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इतना ही नहीं, इस भारी मतदान ने राजनीतिक दलों की धड़कनें भी तेज कर दी हैं, क्योंकि हर दल इसे अपने पक्ष में जनसमर्थन के रूप में देख रहा है। हालांकि इस बंपर मतदान के वास्तविक मायने क्या हैं, यह समझने के लिए तीनों राज्यों का अलग अलग विश्लेषण जरूरी है।सबसे पहले बात असम की करें तो यहां का मतदान प्रतिशत न केवल पिछले चुनावों से अधिक रहा बल्कि कई क्षेत्रों में रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। कुल 126 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 85 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया, जो पहले के चुनावों के मुकाबले अधिक है। खास बात यह रही कि सोलह निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान नब्बे प्रतिशत से भी ऊपर पहुंच गया। दलगांव में तो मतदान लगभग 95 प्रतिशत के करीब रहा, जो राज्य में सबसे अधिक है।

असम में चुनावी मुकाबला मुख्य रूप से दो ध्रुवों के बीच रहा। एक ओर भाजपा के नेतृत्व वाला सत्तारुढ़ गठबंधन है जो लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष गठबंधन सत्ता में वापसी के लिए संघर्षरत है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय दल भी कुछ सीटों पर प्रभाव डालने की स्थिति में हैं।

यहां मतदान का एक महत्वपूर्ण पहलू क्षेत्रीय असमानता के रूप में सामने आया। निचले असम के क्षेत्रों में, जहां अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या अधिक है, वहां मतदान प्रतिशत अत्यधिक रहा। बरपेटा, बोंगाईगांव और धुबरी जैसे जिलों में मतदान नब्बे प्रतिशत से ऊपर दर्ज किया गया। इसके विपरीत ऊपरी असम के क्षेत्रों में मतदान अपेक्षाकृत कम रहा। इससे यह संकेत मिलता है कि चुनावी उत्साह उन क्षेत्रों में अधिक था जहां मुकाबला अधिक तीखा है।

हालांकि मतदान के दौरान कुछ स्थानों पर हिंसा की घटनाएं भी सामने आईं, लेकिन कुल मिलाकर मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही। भारी मतदान को लेकर सत्तारुढ़ नेतृत्व ने इसे ऐतिहासिक बताया और इसे जनता के विश्वास का प्रतीक माना।

अब केरल की बात करें तो यहां का चुनाव परंपरागत रूप से दो प्रमुख गठबंधनों के बीच होता रहा है। इस बार भी मुख्य मुकाबला सत्तारुढ़ वाम मोर्चा और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ मोर्चे के बीच रहा, जबकि तीसरा विकल्प बनने की कोशिश कर रहा भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में लगा है।

केरल में लगभग 77 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया, जो पिछले चुनाव से अधिक है। आंकड़ों के मुताबिक कोझिकोड जिले में सबसे अधिक मतदान दर्ज किया गया, जबकि कुछ क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम मतदान हुआ। केरल में इस बार चुनाव का मुख्य सवाल यह रहा कि क्या सत्तारुढ़ गठबंधन लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटेगा या फिर विपक्ष वापसी करेगा? उच्च मतदान को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों ने अलग अलग दावे किए हैं। सत्तारुढ़ पक्ष इसे अपनी नीतियों के समर्थन के रूप में देख रहा है, जबकि विपक्ष इसे बदलाव की इच्छा का संकेत बता रहा है।

हम आपको बता दें कि उत्तर केरल यानी मलाबार क्षेत्र इस बार भी चुनावी परिणामों की कुंजी माना जा रहा है। यहां की साठ सीटों पर तीनों प्रमुख राजनीतिक धाराओं की नजर है। पिछले चुनाव में इस क्षेत्र में सत्तारुढ़ दल को बड़ी सफलता मिली थी, लेकिन इस बार विपक्ष यहां बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा है। कई सीटों पर कड़ा मुकाबला और अस्सी प्रतिशत से अधिक मतदान इस क्षेत्र को और भी महत्वपूर्ण बना देता है।

अब पुडुचेरी की बात करें तो यहां सबसे अधिक मतदान दर्ज किया गया, जो लगभग नब्बे प्रतिशत के करीब रहा। यह पिछले सभी रिकॉर्ड को पार करता हुआ दिखाई देता है। यहां मुकाबला मुख्य रूप से दो गठबंधनों के बीच है। एक ओर सत्तारुढ़ एनडीए गठबंधन है तो दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष। पुडुचेरी में चुनावी मुद्दों में राज्य का दर्जा, बेरोजगारी और जल प्रदूषण जैसे विषय प्रमुख रहे। इसके अलावा एक नए राजनीतिक दल की एंट्री ने भी चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। उच्च मतदान से यह संकेत मिलता है कि जनता इन मुद्दों को लेकर गंभीर है और बदलाव या स्थिरता में से किसी एक को स्पष्ट रूप से चुनना चाहती है।

तीनों राज्यों के आंकड़ों को मिलाकर देखें तो कुल मिलाकर पांच करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया और कुल एक हजार नौ सौ से अधिक उम्मीदवार मैदान में रहे। यह संख्या इस बात को दर्शाती है कि लोकतंत्र में भागीदारी कितनी व्यापक है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारी मतदान सत्ता परिवर्तन का संकेत है या फिर यह सत्तारुढ़ दलों के प्रति विश्वास को दर्शाता है? चुनावी विशेषज्ञों की राय इस पर बंटी हुई है। कुछ का मानना है कि जब लोग बड़ी संख्या में मतदान करते हैं तो यह बदलाव की इच्छा का संकेत होता है, जबकि अन्य इसे सरकार के प्रति संतोष के रूप में देखते हैं। वैसे कई विश्लेषकों का यह भी कहना है कि तीनों ही राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान जो बात सबसे प्रमुख तौर पर नजर आई वह यह थी कि सरकार के खिलाफ नाराजगी जरूर दिखी लेकिन सरकार बदलने का भाव जनता के बीच नहीं दिखा।

बहरहाल, यह कहा जा सकता है कि असम में क्षेत्रीय ध्रुवीकरण, केरल में परंपरागत मुकाबला और पुडुचेरी में सीधी टक्कर ने इन चुनावों को बेहद रोमांचक और निर्णायक बना दिया है। भारी मतदान ने लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने का काम किया है और यह साफ संकेत दिया है कि जनता अपने अधिकार को लेकर पहले से अधिक सजग है। अब सबकी नजर मतगणना पर टिकी है, क्योंकि असली तस्वीर वही सामने लाएगी जो इस जनभागीदारी के पीछे छिपे जनमत को स्पष्ट करेगी।

अभियान

अज्ञान से ज्ञान तक की ज्योति: महर्षि वाल्मीकि की वाणी और मानवता का शाश्वत मार्ग

अश्विन मास की पूर्णिमा का दिन भारतीय संस्कृति में केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, प्रेरणा और जागरण का प्रतीक है, क्योंकि इसी दिन महर्षि वाल्मीकि की जयंती पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जाती है। यह पर्व हमें उस महापुरुष के जीवन, उनके संघर्ष, उनके ज्ञान और उनकी अमर वाणी को याद करने का अवसर देता है, जिसने न केवल एक महाकाव्य की रचना की, बल्कि संपूर्ण मानवता को जीवन जीने का सही मार्ग भी दिखाया। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक अनुष्ठान, शोभायात्राएं, कथा-कीर्तन और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य समाज में नैतिकता, एकता और आध्यात्मिक चेतना का संचार करना होता है।

महर्षि वाल्मीकि को ‘आदिकवि’ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने संसार के प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना की। यह ग्रंथ केवल भगवान श्रीराम की कथा नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन का दर्पण है, जिसमें कर्तव्य, धर्म, प्रेम, त्याग, मर्यादा और आदर्शों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। रामायण में वर्णित प्रत्येक प्रसंग हमें जीवन के किसी न किसी सत्य से परिचित कराता है और हमें यह सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए।

रामायण को वेदों के समान सम्मान प्राप्त है, क्योंकि इसमें जीवन के हर क्षेत्र का ज्ञान समाहित है। यह महाकाव्य न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें विज्ञान, ज्योतिष, राजनीति, समाजशास्त्र और कला का भी गहन अध्ययन मिलता है। लगभग चौबीस हजार श्लोकों में रचित यह ग्रंथ आज भी विश्व की अनेक भाषाओं में उपलब्ध है और करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। यह भारतीय संस्कृति की आत्मा है, जिसने सदियों से समाज को एकता के सूत्र में बांधे रखा है।

महर्षि वाल्मीकि का जीवन स्वयं में एक अद्भुत परिवर्तन की कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, उनका प्रारंभिक नाम रत्नाकर था, और वे एक डाकू के रूप में जीवन यापन करते थे। अपने परिवार के पालन-पोषण के लिए वे लूटपाट करते थे और इसे अपना कर्तव्य मानते थे। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा क्षण आया, जिसने उनके पूरे अस्तित्व को बदल दिया।

एक दिन उनकी भेंट नारद मुनि से हुई। रत्नाकर ने उन्हें पकड़ लिया और लूटने का प्रयास किया, लेकिन नारद मुनि ने उनसे एक ऐसा प्रश्न पूछा, जिसने उनके अंतर्मन को झकझोर दिया। उन्होंने पूछा कि जिनके लिए तुम यह पाप कर रहे हो, क्या वे तुम्हारे इस पाप में भागीदार बनने को तैयार हैं? यह प्रश्न रत्नाकर के लिए एक आईने की तरह था, जिसमें उन्हें अपने कर्मों की सच्चाई दिखाई दी। जब रत्नाकर ने अपने परिवार से यह प्रश्न किया, तो उन्हें यह जानकर गहरा आघात लगा कि कोई भी उनके पापों का भागीदार बनने को तैयार नहीं है। यह अनुभव उनके जीवन का turning point बना। वे वापस लौटे, नारद मुनि के चरणों में गिर पड़े और उनसे अपने पापों के प्रायश्चित का मार्ग पूछा। तब नारद मुनि ने उन्हें ‘राम’ नाम का जाप करने की सलाह दी।

शुरुआत में रत्नाकर के लिए ‘राम’ नाम लेना कठिन था, इसलिए उन्हें ‘मरा-मरा’ का जाप करने को कहा गया। यह साधारण-सा उपाय उनके जीवन को बदलने वाला सिद्ध हुआ। निरंतर जप और तपस्या के प्रभाव से उनका हृदय शुद्ध होता गया और वे एक महान ऋषि के रूप में परिवर्तित हो गए। वर्षों की कठोर तपस्या के दौरान उनके शरीर पर चीटियों ने बांबी बना ली, और इसी कारण उन्हें ‘वाल्मीकि’ नाम मिला।

यह परिवर्तन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह इस सत्य का प्रमाण है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है, यदि वह सच्चे मन से प्रयास करे। महर्षि वाल्मीकि का जीवन हमें यह सिखाता है कि अतीत चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, वर्तमान में सही निर्णय लेकर भविष्य को उज्ज्वल बनाया जा सकता है।

रामायण की रचना भी एक अद्भुत घटना से जुड़ी है। एक बार महर्षि वाल्मीकि ने एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा, जिसमें से एक को एक शिकारी ने मार दिया। इस घटना से उनके हृदय में गहरी करुणा उत्पन्न हुई और उसी वेदना से उनके मुख से एक श्लोक निकला, जो संस्कृत साहित्य का पहला काव्य श्लोक माना जाता है। यही से काव्य रचना की शुरुआत हुई और उन्होंने रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना की।

रामायण केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के आदर्शों का संग्रह है। इसमें श्रीराम के जीवन के माध्यम से यह बताया गया है कि एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श भाई और एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए। श्रीराम का जीवन त्याग, मर्यादा और सत्य का प्रतीक है, जो हर युग में प्रासंगिक है।

पौराणिक कथाओं में यह भी वर्णित है कि जब श्रीराम ने माता माता सीता का त्याग किया, तब उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली। वहीं उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने ही उन्हें शिक्षा दी और संस्कार दिए। बाद में लव-कुश ने ही श्रीराम के समक्ष रामायण का गायन किया। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान और संस्कार की शक्ति कितनी महान होती है।

महर्षि वाल्मीकि की वाणी आज भी मानवता के लिए एक दीपक के समान है, जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और धर्म का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने यह भी बताया कि मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए और सदैव अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर होना चाहिए।

आज के समय में, जब समाज अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है, तब महर्षि वाल्मीकि की शिक्षाएं और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती हैं। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने भीतर झांकें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। उनका संदेश यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने अतीत से बंधा नहीं है, बल्कि वह अपने वर्तमान को सुधारकर अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकता है।

वाल्मीकि जयंती का यह पावन अवसर हमें यह स्मरण कराता है कि हमें अपने जीवन में उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए। यह केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि आत्मसुधार और आत्मजागरण का अवसर है। यदि हम उनके दिखाए मार्ग पर चलें, तो न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन सुधर सकता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है।

इस प्रकार, महर्षि वाल्मीकि का जीवन और उनकी वाणी आज भी मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चे प्रयास, दृढ़ संकल्प और ईश्वर के प्रति भक्ति से कोई भी व्यक्ति महानता को प्राप्त कर सकता है। उनका संदेश युगों-युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा और हमें यह प्रेरणा देता रहेगा कि हम सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलते हुए एक आदर्श जीवन जीने का प्रयास करें।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

भारत ने 1000 किलोमीटर से अधिक लंबे क्वांटम नेटवर्क का सफल परीक्षण किया, डाटा सुरक्षा के नए युग की शुरुआत

नई दिल्ली। भारत ने क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 1000 किलोमीटर से अधिक लंबे क्वांटम संचार नेटवर्क का सफल परीक्षण कर लिया है। इस उपलब्धि को देश की डिजिटल सुरक्षा प्रणाली और भविष्य की संचार तकनीक के लिए एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। इस सफलता के बाद भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है, जो क्वांटम-आधारित सुरक्षित संचार तकनीक को बड़े पैमाने पर विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

यह पूरा प्रोजेक्ट राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम) के तहत विकसित किया गया है, जिसे केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में मंजूरी दी थी। इस मिशन का उद्देश्य देश में क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जैसी उन्नत तकनीकों को विकसित करना है, ताकि भविष्य में साइबर सुरक्षा को लगभग अभेद्य बनाया जा सके। इसी मिशन के तहत विकसित यह 1000 किलोमीटर से अधिक लंबा क्वांटम नेटवर्क अब तक का सबसे बड़ा सफल परीक्षण माना जा रहा है।

इस नेटवर्क को स्वदेशी स्टार्टअप क्यूएनयू लैब्स द्वारा विकसित तकनीक की मदद से तैयार किया गया है। इसमें क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (QKD) तकनीक का उपयोग किया गया है, जो डेटा को अत्यधिक सुरक्षित बनाती है। इस तकनीक की खासियत यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति या हैकर डेटा को बीच में रोकने या पढ़ने की कोशिश करता है, तो सिस्टम तुरंत उसे पहचान लेता है और संचार प्रक्रिया को सुरक्षित मोड में बदल देता है। इसी वजह से इस तकनीक को भविष्य की सबसे सुरक्षित संचार प्रणालियों में से एक माना जा रहा है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह उपलब्धि केवल तकनीकी सफलता नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस तकनीक के सफल परीक्षण के बाद देश की रक्षा प्रणाली, बैंकिंग नेटवर्क, अंतरिक्ष संचार और सरकारी डेटा सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीक आने वाले समय में पारंपरिक इंटरनेट सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकती है।

इस क्वांटम नेटवर्क की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी दूरी तक सुरक्षित संचार क्षमता है। अब तक क्वांटम तकनीक को सीमित दूरी तक ही प्रभावी माना जाता था, लेकिन भारत ने इसे 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक सफलतापूर्वक लागू करके एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। यह नेटवर्क फाइबर-आधारित और मुक्त-स्थान (free-space) दोनों तकनीकों पर काम करने में सक्षम है, जिससे इसे कठिन भौगोलिक क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों और जल के नीचे भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

विज्ञान विशेषज्ञ डॉ. अभय करंदीकर ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह भारत के क्वांटम मिशन की अपेक्षाओं से कहीं आगे है। उन्होंने कहा कि देश अब 2000 किलोमीटर लंबे क्वांटम नेटवर्क के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जो भविष्य में एक राष्ट्रीय क्वांटम इंटरनेट की नींव रख सकता है।

इस तकनीक की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह क्वांटम एंटैंगलमेंट सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें सूचनाओं का आदान-प्रदान फोटॉन के माध्यम से होता है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ तुरंत पकड़ में आ जाती है, जिससे डेटा चोरी या हैकिंग की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। इसी कारण इसे "अभेद्य एन्क्रिप्शन" तकनीक भी कहा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तकनीक के आने से देश की साइबर सुरक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। वर्तमान समय में डेटा चोरी और साइबर हमले एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं, लेकिन क्वांटम नेटवर्क इन खतरों को काफी हद तक कम करने में सक्षम होगा। विशेष रूप से बैंकिंग, रक्षा, डिजिटल भुगतान और सरकारी संचार में यह तकनीक अत्यंत उपयोगी साबित हो सकती है।

इसके अलावा इस परियोजना के तहत भारत में क्वांटम स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी तेजी से विकसित किया जा रहा है। अब तक 17 स्टार्टअप इस मिशन से जुड़े हैं, जो क्वांटम बायोसेन्सर, फोटॉन सेंसिंग, क्वांटम पोजिशनिंग सिस्टम और एटॉमिक मेमोरी जैसी उन्नत तकनीकों पर काम कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि भारत को इस क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व प्रदान किया जाए।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने भी पिछले वर्षों में इस दिशा में कई प्रयोग किए हैं, जिनमें सीमित दूरी पर क्वांटम सुरक्षित संचार का सफल परीक्षण शामिल है। इन प्रयोगों ने यह साबित किया है कि यह तकनीक वास्तविक परिस्थितियों में भी प्रभावी रूप से काम कर सकती है।

अप्रैल 2023 में शुरू हुए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को 2031 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए सरकार ने लगभग 6000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इस मिशन का उद्देश्य भारत को न केवल क्वांटम तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर एक मजबूत तकनीकी शक्ति के रूप में स्थापित करना भी है।

विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले वर्षों में क्वांटम इंटरनेट पारंपरिक इंटरनेट की तुलना में अधिक सुरक्षित, तेज और विश्वसनीय होगा। इससे न केवल डेटा ट्रांसफर की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि डिजिटल संचार व्यवस्था भी पूरी तरह बदल जाएगी।

इस उपलब्धि के साथ भारत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह भविष्य की तकनीकों में केवल भागीदार नहीं बल्कि अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। यह क्वांटम नेटवर्क परीक्षण देश को डिजिटल सुरक्षा के नए युग में प्रवेश कराने वाला कदम माना जा रहा है, जो आने वाले समय में भारत की तकनीकी क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।

गगनयान मिशन के दूसरे क्रू मॉड्यूल टेस्ट में बड़ी सफलता, भारत के मानव अंतरिक्ष अभियान को मिली नई गति

श्रीहरिकोटा। भारत के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारियों में एक और महत्वपूर्ण सफलता दर्ज की गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने गुरुवार को दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट (IADT-1) सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। यह परीक्षण गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल की सुरक्षा प्रणाली और विशेष रूप से पैराशूट लैंडिंग सिस्टम की वास्तविक परिस्थितियों में कार्यक्षमता को परखने के लिए किया गया था।

इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाने की प्रक्रिया पूरी तरह विश्वसनीय और सुरक्षित हो। गगनयान मिशन में वापसी के दौरान क्रू मॉड्यूल की धीमी और नियंत्रित लैंडिंग के लिए पैराशूट सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रणाली के प्रदर्शन को परखने के लिए यह हाई-लेवल ड्रॉप टेस्ट किया गया।

परीक्षण के दौरान लगभग 5.7 टन वजनी डमी क्रू कैप्सूल को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलिकॉप्टर की मदद से लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। जैसे ही कैप्सूल नीचे की ओर गिरा, पैराशूट सिस्टम सक्रिय हुआ और सभी चरणों में सही तरीके से खुलते हुए कैप्सूल को नियंत्रित गति से समुद्र की सतह तक सुरक्षित पहुंचाया गया। यह प्रक्रिया बिल्कुल वास्तविक मिशन स्थितियों जैसी थी, ताकि किसी भी प्रकार की तकनीकी कमी का पता लगाया जा सके।

ISRO के वैज्ञानिकों के अनुसार यह परीक्षण पूरी तरह सफल रहा और सभी सुरक्षा पैरामीटर सही पाए गए। इससे पहले भी अगस्त 2025 में इसी तरह का पहला एयर ड्रॉप टेस्ट किया गया था, जिसमें पैराशूट प्रणाली का प्रारंभिक प्रदर्शन जांचा गया था। लगातार दूसरे सफल परीक्षण ने गगनयान मिशन की तैयारियों को और अधिक मजबूत बना दिया है।

गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसके तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा (Low Earth Orbit) में भेजने और सुरक्षित वापस लाने की योजना है। इस मिशन के तहत तीन भारतीय वायुसेना के पायलटों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जो लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीन दिनों तक अंतरिक्ष में रहेंगे और फिर हिंद महासागर में सुरक्षित लैंडिंग करेंगे।

इस मिशन के लिए चुने गए पायलटों में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी शामिल हैं, जिन्होंने पहले एक्सियम मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की यात्रा की थी। उनके अनुभव को इस मिशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुल मिलाकर चार पायलटों को इस मिशन के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिनमें से अंतिम चयन मिशन फ्लाइट से पहले किया जाएगा।

ISRO ने इस मिशन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की योजना बनाई है। इसके तहत पहले दो बिना चालक (uncrewed) टेस्ट फ्लाइट भेजी जाएंगी, जिनमें सिस्टम की पूरी क्षमता और सुरक्षा की जांच की जाएगी। इसके बाद एक रोबोटिक मिशन भेजा जाएगा, जो मानव मिशन से पहले अंतिम परीक्षण के रूप में काम करेगा। इन सभी चरणों के सफल होने के बाद ही मानवयुक्त उड़ान को हरी झंडी दी जाएगी। मिशन की कुल लागत लगभग 20,193 करोड़ रुपये आंकी गई है, जो इसे भारत के सबसे बड़े अंतरिक्ष कार्यक्रमों में से एक बनाती है। इस परियोजना का उद्देश्य केवल अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजना ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष तकनीक में देश को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना भी है।

ISRO का मानना है कि गगनयान मिशन भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने वाला है। इससे पहले भारत ने चंद्रयान और मंगलयान जैसी उपलब्धियों के माध्यम से विश्व स्तर पर अपनी वैज्ञानिक क्षमता का प्रदर्शन किया है, लेकिन मानव अंतरिक्ष उड़ान एक पूरी तरह नई चुनौती है।

विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह के एयर ड्रॉप टेस्ट मिशन की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष से लौटते समय यदि पैराशूट सिस्टम में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता है। इसलिए इस चरण का सफल होना गगनयान मिशन की दिशा में एक बड़ा सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

अब ISRO अगले चरण के परीक्षणों की तैयारी कर रहा है, जिसमें और अधिक जटिल सिस्टम चेक और बिना चालक उड़ान परीक्षण शामिल होंगे। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि तय समयसीमा के अनुसार भारत 2027 तक अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लेगा।

इस उपलब्धि के साथ भारत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

सूरत में सिंधी भाषा मान्यता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया, मातृभाषा संरक्षण का लिया संकल्प

सूरत। शहर में आज भारतीय सिंधु सभा और सूरत सिंधी पंचायत के संयुक्त तत्वावधान में सिंधी भाषा मान्यता दिवस उत्साह, श्रद्धा और सांस्कृतिक गर्व के साथ मनाया गया। हर वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाने वाला यह विशेष दिवस इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई थी। इस ऐतिहासिक उपलब्धि की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग, युवा, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक शामिल हुए और मातृभाषा के संरक्षण का संकल्प दोहराया।

कार्यक्रम का वातावरण पूरी तरह सांस्कृतिक ऊर्जा और भावनात्मक जुड़ाव से भरा हुआ दिखाई दिया। आयोजन स्थल पर सिंधी संस्कृति से जुड़े गीत, विचार और परंपराओं का समावेश देखने को मिला, जिससे उपस्थित लोगों में अपनी भाषा और पहचान को लेकर गर्व की भावना और अधिक प्रबल हो गई। कार्यक्रम में समाज के अग्रणी नेता हरीश लालवाणी ने मातृभाषा के महत्व पर

विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि कोई भी भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती, बल्कि वह एक सभ्यता, संस्कृति और पहचान की आत्मा होती है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यदि कोई समाज अपनी मातृभाषा को भूलने लगता है तो वह धीरे-धीरे अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भी दूर होने लगता है। उन्होंने विशेष रूप से घरों में सिंधी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने की अपील की और कहा कि बच्चों की पहली पाठशाला घर होता है, इसलिए भाषा का पहला संस्कार भी वहीं से मिलता है। उन्होंने कहा कि माताएं इस दिशा में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकती हैं, क्योंकि यदि बच्चे बचपन से अपनी मातृभाषा सुनते और बोलते हैं तो वह भाषा उनके जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाती है।

कार्यक्रम में उपस्थित अन्य वक्ताओं ने भी मातृभाषा के संरक्षण को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज के समय में अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बढ़ते प्रभाव के कारण क्षेत्रीय भाषाएं और मातृभाषाएं धीरे-धीरे कमजोर हो रही हैं। यह केवल भाषा का संकट नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत के क्षरण का भी संकेत है। वक्ताओं ने कहा कि यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों और परंपराओं से अनभिज्ञ हो सकती हैं। इस अवसर पर यह भी चर्चा की गई कि भाषा केवल बोलचाल का माध्यम नहीं होती, बल्कि उसमें इतिहास, परंपरा, लोककथाएं, साहित्य और जीवन मूल्यों का पूरा संसार छिपा होता है। सिंधी भाषा भी अपने आप में एक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे संरक्षित करना हर समाज के सदस्य की जिम्मेदारी है। वक्ताओं ने कहा कि भाषा के बिना संस्कृति अधूरी है और संस्कृति के बिना समाज की पहचान कमजोर पड़ जाती है। कार्यक्रम में सूरत सिंधी पंचायत के अध्यक्ष वासुदेव डी. गोपालानी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इसके अलावा भगवानदास भागचंदानी, नानकराम अटलानी, घनश्यामभाई खट्टर, गोरधनभाई, विष्णुभाई, मदनभाई, लीलाराम आहूजा, मयूर होतावानी, त्रिलोकभाई, सुनीताबेन ठाढानी, पालकबेन और तरुणा वाधवानी सहित कई समाजसेवियों ने कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई और अपने विचार साझा किए।

कार्यक्रम के दौरान भारतीय सिंधु सभा के प्रांत सिंधु दर्शन यात्रा के समन्वयक प्रताप गोपालानी ने आगामी सिंधु दर्शन यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य समाज के लोगों को उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस यात्रा से जुड़कर अपनी संस्कृति को समझें और उसे आगे बढ़ाने में योगदान दें। समारोह में यह भी कहा गया कि आधुनिकता के इस दौर में तकनीक और वैश्वीकरण ने भले ही दुनिया को करीब ला दिया हो, लेकिन इससे स्थानीय भाषाओं पर दबाव भी बढ़ा है। ऐसे में यह आवश्यक है कि हर परिवार अपनी मातृभाषा को दैनिक जीवन में शामिल करे और बच्चों को इसके महत्व के बारे में बताए।

कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान और शांति मंत्र के साथ किया गया, जिसमें सभी उपस्थित लोगों ने सामूहिक रूप से मातृभाषा संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया। पूरे आयोजन ने यह संदेश दिया कि भाषा केवल संचार का साधन नहीं, बल्कि समाज की आत्मा होती है, और इसे बचाना हर पीढ़ी की जिम्मेदारी है।

मेरठ में बेटी के तलाक के बाद परिवार का अनोखा स्वागत ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न का वीडियो वायरल हो गया

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। समाज में जब बेटी का तलाक होता है, तो माता-पिता समेत पूरा परिवार दुखी होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक पिता ने सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए एक नया चलन शुरू किया है। बेटी के तलाक पर शोक मनाने के बजाय, परिवार ने ढोल-नगाड़ों और फूलों से उसका स्वागत किया और इस अवसर को उत्सव में बदल दिया।

इस अनोखे स्वागत का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग पिता के इस प्रगतिशील विचार की सराहना कर रहे हैं। मेरठ के शास्त्रीनगर निवासी प्रतीक्षा का विवाह 2018 में शाहजहांपुर के मेजर गौरव अग्निहोत्री से हुआ था। दंपति का एक बेटा भी है, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल वालों की ओर से उत्पीड़न और विवाद शुरू हो गए।

लंबे कानूनी संघर्ष के बाद, अदालत ने 4 अप्रैल को उनके तलाक को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी। कानूनी लड़ाई जीतने के बाद जब प्रतीक्षा घर लौटीं, तो उनके पिता ने उन्हें हार न मानने के बजाय एक नई शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित किया।

प्रतीक्षा के पिता, जो एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, ने इस अवसर को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी बेटी की तस्वीर वाली काली टी-शर्ट पहनी थी, जिस पर लिखा था, "मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूँ।" प्रतीक्षा के घर पहुँचते ही परिवार के सदस्यों ने नाच-गाना किया और उस पर फूल बरसाए। आसपास के लोग यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। चूंकि समाज में तलाक को आमतौर पर शर्मनाक या दुखद घटना माना जाता है, इसलिए पिता ने इस प्रेरणादायक कदम के बारे में कहा, "मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता। अगर वह छह साल के वैवाहिक जीवन में नाखुश थी और परेशान होकर घर लौटी है, तो मैं उसे और कष्ट नहीं सहने देना चाहता। मेरा उद्देश्य समाज को यह संदेश देना है कि बेटियाँ बेटों के समान होती हैं और वे समान प्रेम, सम्मान और समर्थन की हकदार हैं।"

नेटिज़न्स इस पिता को "असली हीरो" कह रहे हैं और उनका कहना है कि अगर हर परिवार अपनी बेटियों के साथ इस तरह खड़ा रहे, तो घरेलू हिंसा और सामाजिक कलंक के खिलाफ लड़ाई आसान हो जाएगी। इसे ही कहते हैं कि बेटी प्रेम का सागर होती है।

सोना वायदा में 644 रुपये और चांदी वायदा में 1371 रुपये की गिरावट: क्रूड ऑयल वायदा 162 रुपये तेज

मुंबई: देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 154435.51 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 22346.25 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 132089.15 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का अप्रैल वायदा 36696 पॉइंट के स्तर पर ट्रेड हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 3533.97 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 13794.60 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा 152685 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 152990 रुपये और नीचे में 151745 रुपये पर पहुंचकर, 153434 रुपये के पिछले बंद के सामने 644 रुपये या 0.42 फीसदी घटकर 152790 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-गिनी अप्रैल वायदा 227 रुपये या 0.19 फीसदी औंधकर 122192 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल अप्रैल वायदा 28 रुपये या 0.18 फीसदी औंधकर 15304 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी मई वायदा 150905 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 151755 रुपये और नीचे में 150414 रुपये पर पहुंचकर, 667 रुपये या 0.44 फीसदी औंधकर 151405 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन अप्रैल वायदा प्रति 10 ग्राम 151567 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 152183 रुपये और नीचे में 150848 रुपये पर पहुंचकर, 152366 रुपये के पिछले बंद के सामने 533 रुपये या 0.35 फीसदी औंधकर 151833 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा सत्र के आरंभ में 242515 रुपये के भाव पर खूलकर, 243704 रुपये के दिन के उच्च और 239546 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 243768 रुपये के पिछले बंद के सामने 1371 रुपये या 0.56 फीसदी लुढ़ककर 242397 रुपये प्रति किलो बोला गया। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 1307 रुपये या 0.53 फीसदी की गिरावट के साथ 244629 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 1112 रुपये या 0.45 फीसदी लुढ़ककर 244750 रुपये प्रति किलो बोला गया।

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 22346.25 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 132089.15 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 13794.60 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 36696 पॉइंट के स्तर

मेटल वर्ग में 2534.26 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा अप्रैल वायदा 15.05 रुपये या 1.26 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 1208 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि जस्ता अप्रैल वायदा 1.05 रुपये या 0.32 फीसदी की तेजी के संग 331.9 रुपये प्रति किलो हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम अप्रैल वायदा 3.6 रुपये या 1.02 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 357.85 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा अप्रैल वायदा 1.2 रुपये या 0.62 फीसदी औंधकर 193.3 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 5824.52 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 9200 रुपये के भाव पर खूलकर, 9344 रुपये के दिन के उच्च और 9066 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 162 रुपये या 1.81 फीसदी की तेजी के संग 9095 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी अप्रैल वायदा 158 रुपये या 1.77 फीसदी की बढ़त के साथ 9092 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस अप्रैल वायदा 251.6 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 252.7 रुपये और नीचे में 247 रुपये पर पहुंचकर, 250.6 रुपये के पिछले बंद के सामने 3.5 रुपये या 1.4 फीसदी औंधकर 247.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी अप्रैल वायदा 3.3 रुपये या 1.32 फीसदी लुढ़ककर 247.3 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल अप्रैल वायदा 1002 रुपये पर खूलकर, 20 पैसे या 0.02 फीसदी बढ़कर 1013.8 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 9509.15 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 4285.44 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 1960.65 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 371.82 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 24.94 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 176.85 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 4693.05 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1116.67 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 8907 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 53896 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 26303 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 379956 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 56845 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 7200 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 20626 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 82505 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17825 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 49647 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स अप्रैल वायदा 36696 पॉइंट पर खूलकर, 36696 के उच्च और 36696 के नीचले स्तर को छूकर, 343 पॉइंट बढ़कर 36696 पॉइंट के स्तर पर ट्रेड हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल अप्रैल 10000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 21.5 रुपये की बढ़त के साथ 207 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 250 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1 रुपये की गिरावट के साथ 9.85 रुपये हुआ।

सोना अप्रैल 160000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 208.5 रुपये की गिरावट के साथ 1447.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 42 रुपये की बढ़त के साथ 657.5 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1250 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 5.56 रुपये की बढ़त के साथ 11.9 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 335 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 71 पैसे के सुधार के साथ 3.71 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल अप्रैल 8000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 19.1 रुपये की गिरावट के साथ 116.4 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 250 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 80 पैसे के सुधार के साथ 11.1 रुपये हुआ।

सोना अप्रैल 140000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 21 रुपये की गिरावट के साथ 771.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 180000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 53 रुपये की बढ़त के साथ 379 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1150 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 43 पैसे की नरमी के साथ 7.53 रुपये हुआ।

अहमदाबाद में दो मासूम बच्चियों की संदिग्ध मौत से हड़कंप, जहर की पुष्टि के बाद हत्या या आत्महत्या के एंगल से जांच तेज

अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद शहर के चांदखेड़ा इलाके में दो मासूम बच्चियों की संदिग्ध मौत के मामले ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। शुरुआती जांच में जिसे फूड पॉइजनिंग का मामला माना जा रहा था, वह अब एक गंभीर आपराधिक जांच में बदल चुका है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि बच्चियों की मौत किसी जहरीले पदार्थ के सेवन से हुई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले को हत्या, आत्महत्या या साजिश—तीनों संभावनाओं के नजरिए से जांचना शुरू कर दिया है।

इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर जहर बच्चियों के खाने में कैसे पहुंचा—क्या यह पहले से डोसे या उसके घोल में मौजूद था, या फिर किसी ने बाद में उसमें जहरीला पदार्थ मिलाया।

फूड पॉइजनिंग की थ्योरी खारिज, जहर से मौत की पुष्टि

पुलिस और फॉरेंसिक टीम की शुरुआती जांच में यह बात साफ हो गई है कि यह सामान्य फूड पॉइजनिंग का मामला नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, बच्चियों के शरीर में सल्फास जैसे अत्यधिक जहरीले कीटनाशक के अंश पाए गए हैं। सल्फास आमतौर पर अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अत्यधिक जहरीला होता है।

इसी आधार पर अब जांच का पूरा फोकस इस बात पर है कि यह जहरीला पदार्थ शरीर में कैसे पहुंचा। क्या यह भोजन में मिलाया गया था या किसी अन्य माध्यम से बच्चियों को

दिया गया, इस पर जांच एजेंसियां गहराई से काम कर रही हैं।

घर से सल्फास बरामद, जांच का दायरा बढ़ा

पुलिस को जांच के दौरान परिवार के घर से सल्फास की गोलियां भी बरामद हुई हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। इस बरामदगी के बाद जांच और भी गंभीर हो गई है। अब यह संभावना भी खंगाली जा रही है कि जहर घर में पहले से मौजूद था या इसे हाल ही में लाया गया था।

इसी बीच, पुलिस ने बच्चियों के माता-पिता विमल प्रजापति और भावना प्रजापति के ब्लड सैंपल भी जांच के लिए भेजे थे, जिनमें जहरीले तत्वों के संकेत मिलने की बात सामने आई है। हालांकि, इसको लेकर विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

डोसे से जुड़ा रहस्य और समयरेखा

जांच में यह भी सामने आया है कि घटना से ठीक एक रात पहले 1 अप्रैल को पिता विमल प्रजापति एक डेयरी से डोसे का घोल लेकर घर आया था। इसके बाद परिवार ने डोसा खाया था। इसी वजह से शुरुआत में पूरे मामले को फूड पॉइजनिंग माना गया था। लेकिन अब FSL रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि मौत का कारण सामान्य खाना नहीं बल्कि जहरीला पदार्थ है। इसके बाद जांचकर्ता अब इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि क्या जहर डोसे के घोल में मिलाया गया था या फिर भोजन के बाद किसी अन्य तरीके से बच्चियों के शरीर में पहुंचा।

हत्या, आत्महत्या या साजिश—तीनों एंगल पर जांच

पुलिस के सामने अब तीन मुख्य एंगल हैं—पहला, यह एक सोची-समझी हत्या हो सकती है; दूसरा, यह आत्महत्या का मामला हो सकता है जिसमें बच्चों को भी शामिल किया गया; और तीसरा, यह किसी पारिवारिक या बाहरी साजिश का परिणाम हो सकता है।

जांच एजेंसियां इस बात को भी खंगाल रही हैं कि क्या परिवार में कोई तनाव या विवाद लंबे समय से चल रहा था, जिसने इस घटना को जन्म दिया।

मेडिकल स्टोर और सीसीटीवी फुटेज की जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच ने आसपास के मेडिकल स्टोर और सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। विशेष रूप से उस मेडिकल स्टोर पर ध्यान दिया जा रहा है जो बच्चियों की मां के परिवार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है।

पुलिस को शक है कि जहरीले पदार्थ का स्रोत इसी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना से पहले या बाद में कोई संदिग्ध गतिविधि हुई थी या नहीं।

आर्थिक तंगी और पारिवारिक तनाव की भूमिका

जांच में यह भी सामने आया है कि परिवार लंबे समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। पिता विमल प्रजापति बेरोजगार थे और मॉडलिंग के क्षेत्र में करियर बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ ही उनके ऑस्ट्रेलिया जाने की योजना की भी जानकारी सामने आई है।

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या आर्थिक दबाव, मानसिक तनाव या पारिवारिक विवाद इस घटना के पीछे कोई भूमिका निभा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी संकेत मिले हैं कि परिवार में बेटे की चाह और दूसरी बेटी के जन्म के बाद तनाव बढ़ा था, जिसे भी एक संभावित कारण के रूप में देखा जा रहा है।

बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत अहमदाबाद मण्डल से चलने/गुजरने वाली ट्रेनें प्रभावित

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्री सुविधाओं के उन्नयन एवं रेलवे अवसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत गेरतपुर–अहमदाबाद खंड पर प्रीकास्टेड पोर्टल बीम की स्थापना हेतु दिनांक 13 अप्रैल 2026 को प्रातः 10:15 बजे से 13:45 बजे तक (03 घंटे 30 मिनट) ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। जिसके कारण निम्नलिखित ट्रेनें प्रभावित रहेगी।

शॉर्ट टर्मिनेशन / ओरिजिनेशन ट्रेनें

▸▸ट्रेन संख्या 20901 मुंबई सेंट्रल–गांधीनगर केपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस को 13.04.2026 को वटवा स्टेशन पर समाप्त (शॉर्ट टर्मिनेट) किया जाएगा तथा वटवा–गांधीनगर केपिटल के बीच निरस्त रहेगी।

▸▸ट्रेन संख्या 20902 गांधीनगर केपिटल–मुंबई सेंट्रल वंदे भारत

एक्सप्रेस को 13.04.2026 को वटवा स्टेशन से प्रारंभ किया जाएगा तथा गांधीनगर केपिटल–वटवा के बीच निरस्त रहेगी।

पुनर्निर्धारण (Rescheduling)

▸▸ट्रेन संख्या 12009 मुंबई सेंट्रल–अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस 13.04.2026 को मुंबई सेंट्रल से 1 घंटा 15 मिनट विलंब से प्रस्थान करेगी।

निरस्त ट्रेनें (Cancelled Trains)

▸▸ट्रेन संख्या 69102 वटवा–वडोदरा मेमू 13.04.2026 को निरस्त रहेगी।

▸▸ट्रेन संख्या 69115 वडोदरा–वटवा मेमू 13.04.2026 को निरस्त रहेगी।

▸▸ट्रेन संख्या 22959 वडोदरा–जामनगर इंटरसिटी 12.04.2026 को निरस्त रहेगी।

▸▸ट्रेन संख्या 22960 जामनगर–वडोदरा इंटरसिटी 13.04.2026 को निरस्त रहेगी।

आंशिक निरस्त (Partial Cancellation)

▸▸ट्रेन संख्या 19033 बलसाड़–अहमदाबाद गुजरात क्वीन 13.04.2026 को वडोदरा–अहमदाबाद के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

विनियमन (Regulation of Trains)

▸▸ट्रेन संख्या 19436 आसनसोल–अहमदाबाद एक्सप्रेस 13.04.2026 को वडोदरा मण्डल में 2 घंटा 10 मिनट रेगुलेट की जाएगी।

▸▸ट्रेन संख्या 12834 हावड़ा–अहमदाबाद एक्सप्रेस 13.04.2026 को वडोदरा मण्डल में 2 घंटा 10 मिनट रेगुलेट की जाएगी।

▸▸ट्रेन संख्या 12478 श्री माता वैष्णो देवी कटरा–जामनगर एक्सप्रेस 13.04.2026 को वडोदरा मण्डल में 1 घंटा 45 मिनट रेगुलेट की जाएगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेनों के समय, ठहराव एवं अन्य अद्यतन जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

सामाजिक न्याय के संदेश को शब्दों में पिरोते कर्मचारी भावनगर मंडल में आंबेडकर जयंती पर निबंध प्रतियोगिता

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा रेलवे कम्युनिटी हॉल, भावनगर में आज दिनांक 10 अप्रैल 2026 को प्रातः 11:00 बजे भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में "डॉ. बी.आर. आंबेडकर : भारत में सामाजिक न्याय के वास्तुकार" विषय पर निबंध प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में भावनगर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा अपने विचारों के माध्यम से डॉ. आंबेडकर के सामाजिक न्याय, समानता एवं संवैधानिक मूल्यों से संबंधित सिद्धांतों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। प्रतिभागियों ने अपने लेखन के माध्यम से समाज में समरसता एवं न्याय की स्थापना में डॉ. आंबेडकर के योगदान को रेखांकित किया।

यह कार्यक्रम मंडल रेल प्रबंधक, भावनगर श्री दिनेश वर्मा जी की प्रेरणा एवं वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री हुबलाल जगन जी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।

प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। विजेताओं को आगामी डॉ. बी.आर. आंबेडकर जयंती समारोह के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा।

इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने डॉ. आंबेडकर के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने तथा सामाजिक समरसता, समानता एवं न्याय को बढ़ावा देने का संकल्प लिया।

सूरत में गीता ज्ञान का भव्य शुभारंभ: "कृष्णं वंदे जगतगुरुम्" थीम के साथ तीन दिवसीय आध्यात्मिक आयोजन की शुरुआत

सूरत शहर एक बार फिर आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति के रंग में रंग गया है, जहां सोशल आर्मी ग्रुप की ओर से त्रिदिवसीय श्रीमद् भगवद् गीता कोर्स का भव्य शुभारंभ किया गया। संपदा फेस्टिविटी स्थल पर 9, 10 और 11 अप्रैल को आयोजित इस कार्यक्रम ने पहले ही दिन से श्रद्धालुओं और युवाओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। "कृष्णं वंदे जगतगुरुम्" की भावपूर्ण थीम के साथ शुरू हुए इस आयोजन में भक्ति, ज्ञान और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का अद्भुत संगम देखने को मिला।

कार्यक्रम के पहले दिन ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु और युवा उपस्थित हुए, जिससे पूरा स्थल आध्यात्मिक वातावरण में डूब गया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि युवाओं को श्रीमद् भगवद् गीता के शाश्वत ज्ञान से जोड़कर जीवन में सकारात्मक दिशा देना है। इस पहल को समाज में बढ़ती मानसिक तनाव, नकारात्मक सोच और दिशाहीनता के बीच एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

मुख्य वक्ता पारसभाई पांधी ने अपने संबोधन में गीता के गूढ़ संदेशों को सरल भाषा में समझाते हुए कहा कि जीवन में संतुलन, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण तभी विकसित हो सकता है जब

व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखे। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे भौतिक सफलता के साथ-साथ आध्यात्मिक उन्नति पर भी ध्यान दें, क्योंकि वही जीवन को वास्तविक अर्थ प्रदान करती है।

इस अवसर पर भक्ति का वातावरण उस समय और भी अधिक गहरा हो गया जब गुजरात की प्रसिद्ध गायिका उर्वशीबेन रादड़िया और गायक ऋषभ अग्रावत ने एक से बढ़कर एक कृष्ण भजनों की प्रस्तुति दी। उनके मधुर स्वर और भक्ति से भरे गीतों ने पूरे माहौल को कृष्णमय बना दिया। श्रद्धालु भजनों में इतने डूब गए कि पूरा पंडाल "हरे कृष्ण" के जयकारों से गूंज उठा।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी इस आयोजन को विशेष बना दिया। नृत्य कलाकार अमीबेन पटेल और उनकी टीम ने भगवान श्रीकृष्ण के जीवन प्रसंगों पर आधारित मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया, जिसने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। रासलीला और कृष्ण लीला के दृश्यों ने लोगों को धार्मिक अनुभूति के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत से भी जोड़ा।

इस भव्य आयोजन में शहर के कई गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही, जिनमें ईश्वरभाई धोलकिया, घनश्यामभाई शंकर, धीरुभाई नारोला, कनैयालाल नारोला, राकेशभाई दुधात, अश्विनभाई सभाया और पियूषभाई केवडिया प्रमुख रहे। कार्यक्रम की गरिमा उस समय और बढ़ गई जब सूरत शहर के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत भी इस आयोजन में शामिल हुए और उन्होंने आयोजन की सराहना की। आयोजकों के अनुसार इस तीन दिवसीय गीता कोर्स का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं में बढ़ती नकारात्मक सोच, तनाव और भटकाव को दूर कर उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से सही दिशा प्रदान करना है। गीता के उपदेशों को आधुनिक जीवन से जोड़कर यह संदेश दिया जा रहा है कि जीवन में केवल आर्थिक सफलता ही नहीं, बल्कि संस्कार, नैतिक मूल्य और मानसिक शांति भी उतनी ही आवश्यक है।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि श्रीमद् भगवद् गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन प्रबंधन का एक महान ग्रंथ है, जो व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहने की प्रेरणा देता है। अर्जुन और श्रीकृष्ण के संवाद के माध्यम से दिए गए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे।

सोशल आर्मी ग्रुप की यह पहल समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। आयोजन से जुड़े लोगों का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम युवाओं को न केवल आध्यात्मिक रूप से मजबूत करते हैं, बल्कि उन्हें जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझने में भी मदद करते हैं।

तीन दिनों तक चलने वाला यह गीता कोर्स आने वाले दिनों में और भी कई प्रेरणादायक सत्रों, भक्ति संध्याओं और संवाद कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ेगा। श्रद्धालुओं में इसे लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि यह आयोजन सूरत में आध्यात्मिक जागरूकता का एक नया अध्याय लिखेगा।

भावनगर – हरिद्वार के बीच 12 अप्रैल से प्रत्येक रविवार को चलेगी "साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन", टिकटों की बुकिंग 10 अप्रैल, 2026 (शुक्रवार) से प्रारंभ होगी

यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि में अतिरिक्त यात्री सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ट्रेन ऑन डिमांड (TOD) के अंतर्गत विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन विशेष किराया (Special Fare) पर संचालित की जाएगी।

यात्रियों की सुविधा हेतु पश्चिम रेलवे द्वारा भावनगर टर्मिनस और हरिद्वार के बीच "साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन" संचालित की जाएगी। यह सेवा अप्रैल 2026 से मई 2026 के मध्य दोनों दिशाओं में कुल 8-8फेरों के साथ चलाई जाएगी। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार ट्रेनों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है—

ट्रेन नंबर 09271 भावनगर टर्मिनस – हरिद्वार साप्ताहिक स्पेशल 12 अप्रैल, 2026 से 31 मई, 2026 तक संचालित होगी। यह ट्रेन भावनगर टर्मिनस से प्रत्येक रविवार को प्रातः 4.25 बजे प्रस्थान कर सोमवार को दोपहर 15.00 बजे हरिद्वार पहुंचेगी।

इसी प्रकार वापसी में ट्रेन संख्या 09272 हरिद्वार– भावनगर साप्ताहिक स्पेशल 13 अप्रैल, 2026 से 01 जून, 2026 तक संचालित होगी। यह ट्रेन हरिद्वार से प्रत्येक सोमवार को सायं 16.25 बजे प्रस्थान कर बुधवार को प्रातः 04.35 बजे भावनगर टर्मिनस पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में सिहोर, धोला, बोटाद, सुरेन्द्रनगर गेट, विरमगाम, आम्बली रोड, गांधीनगर कैपिटल, महेसाना, पालनपुर जं., आबूरोड, पिण्डवाड़ा, फालना, मारवाड़ जं., पाली मारवाड़, लूनी जं., जोधपुर जं., गोटन, मेड़ता रोड जं., डेगाना जं., छोटी खाटू, डीडवाना, लाडनूं, सुजानगढ़, रतनगढ़ जं., चूरू, सादुलपुर जं., सिवानी, हिसार जं., भिवानी जं., कलानौर कलां, रोहतक जं., पानीपत जं., अम्बाला कैंट जं., सहारनपुर जं. एवं रूड़की स्टेशनों पर ठहरेगी। ट्रेन में सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर तथा जनरल श्रेणी के कोच उपलब्ध रहेंगे।

ट्रेन नंबर 09271 के लिए टिकटों की बुकिंग 10 अप्रैल, 2026 (शुक्रवार) सायं 17.00 बजे से यात्री आरक्षण केंद्रों एवं आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रारंभ होगी। यात्रीगण ट्रेन के समय, ठहराव एवं संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in पर अवलोकन कर सकते हैं। मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने यात्रियों से अपील की है कि वे इस विशेष ट्रेन सेवा का अधिकतम लाभ उठाकर अपनी यात्रा को सुगम एवं सुविधाजनक बनाएं।

सूरत के केमिकल सेक्टर में बड़ा कदम: SGCCI–केमेक्सिल के बीच 5 साल का MoU, हर साल लगेगा केमिकल एंड फार्मा एक्सपो

सूरत के औद्योगिक क्षेत्र के लिए शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026 का दिन एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्ज हो गया है। दक्षिण गुजरात के व्यापारिक संगठन सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत कार्यरत केमेक्सिल के बीच पांच वर्षों के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता न केवल सूरत के केमिकल उद्योग को नई दिशा देगा, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार करेगा। यह MoU मुंबई स्थित केमेक्सिल मुख्यालय में दोनों संस्थाओं के वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। समझौते को सूरत के औद्योगिक विकास की दिशा में एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग के नए अवसर खोल सकता है।

इस साझेदारी की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि अब हर वर्ष सूरत में 'केमिकल एंड फार्मा एक्सपो' का आयोजन किया जाएगा। इस एक्सपो के माध्यम से सूरत के केमिकल और फार्मा उद्योग को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक अपनी पहुंच बनाने का सीधा अवसर मिलेगा। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्लेटफॉर्म स्थानीय इकाइयों को वैश्विक खरीदारों, निवेशकों और तकनीकी विशेषज्ञों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा।

SGCCI के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने इस अवसर पर कहा कि यह समझौता सूरत के केमिकल सेक्टर को एक नई पहचान दिलाने वाला साबित होगा। उन्होंने बताया कि एक्सपो के जरिए छोटे और मध्यम उद्योगों को भी वैश्विक मंच मिलेगा, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी और निर्यात के नए रास्ते खुलेंगे। इस MoU के तहत अगले पांच वर्षों में दोनों संगठन कई प्रमुख क्षेत्रों पर मिलकर काम करेंगे। इनमें सबसे अहम है एक्सपोर्ट गाइडेंस, जिसके तहत उद्यमियों को वैश्विक बाजार की नीतियों, मांग और ट्रेंड्स की जानकारी दी जाएगी, ताकि वे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इसके अलावा नियमित रूप से सेमिनार, वर्कशॉप और मेंटरिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे, जिससे उद्योगों को तकनीकी और व्यावसायिक मार्गदर्शन मिल सके।

नीतिगत स्तर पर भी यह साझेदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोनों संस्थाएं मिलकर केमिकल सेक्टर से जुड़े पॉलिसी मुद्दों पर सरकार के साथ समन्वय करेंगी, ताकि स्थानीय उद्योगों को आवश्यक सहायता और अनुकूल माहौल मिल सके। इससे न केवल व्यापारिक सुगमता बढ़ेगी, बल्कि निवेश के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे।

इस मौके पर चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से मानद मंत्री बिजल जरीवाला, मानद कोषाध्यक्ष सीए मितिश मोदी, सचिव पॉलिक देसाई और ई.जे. थॉमस मौजूद रहे। वहीं, केमेक्सिल की ओर से चेयरमैन सतीश वाघ, वाइस चेयरमैन अंकित पटेल, डायरेक्टर जनरल रघुवीर किनी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विशाल गंजू ने इस साझेदारी को सूरत के औद्योगिक भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया।

केमेक्सिल के चेयरमैन ने भरोसा जताया कि यह साझेदारी सूरत के केमिकल सेक्टर को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में न केवल व्यापार बढ़ेगा, बल्कि नई तकनीक, अनुसंधान और विदेशी निवेश के रास्ते भी खुलेंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि सूरत पहले से ही देश के प्रमुख केमिकल और टेक्सटाइल हब के रूप में जाना जाता है, और यह MoU इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। एक्सपो और निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों के जरिए स्थानीय उद्योगों को वैश्विक पहचान मिलने की संभावना और भी मजबूत हो गई है।

कुल मिलाकर, यह समझौता सूरत के औद्योगिक विकास के लिए एक नई शुरुआत माना जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में शहर की आर्थिक तस्वीर को और अधिक मजबूत और प्रतिस्पर्धी बना सकता है।

श्री रामाश्रय पाण्डेय ने पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक का कार्यभार ग्रहण किया

भारतीय रेल इंजीनियर्स सेवा (IRSE) के 1990 बैच के वरिष्ठ अधिकारी श्री रामाश्रय पाण्डेय ने शुक्रवार, 10 अप्रैल, 2026 को पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक का कार्यभार ग्रहण किया। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले आप पूर्व मध्य रेलवे, पटना में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण/दक्षिण) के पद पर कार्यरत थे।

अपने उत्कृष्ट कैरियर के दौरान श्री पाण्डेय ने उत्तर पूर्व रेलवे के वाराणसी मंडल में मंडल रेल प्रबंधक (DRM) के रूप में तथा उत्तर रेलवे, नई दिल्ली में मुख्य इंजीनियर के पद पर कार्य किया है। आपने गोरखपुर एवं समस्तीपुर में उप मुख्य इंजीनियर, रेलवे बोर्ड में सदस्य इंजीनियरिंग के विशेष कार्याधिकारी (OSD), रेलवे बोर्ड में निदेशक सतर्कता तथा हाजीपुर में उप मुख्य सतर्कता अधिकारी सहित अनेक महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएँ दी हैं। आप रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) में ग्रुप जनरल मैनेजर के रूप में भी कार्यरत रहे, जहाँ आपने कई महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया।

श्री पाण्डेय आईआईटी रुड़की से बी.टेक. तथा आईआईटी दिल्ली से एम.टेक. की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। रेल परिचालन तथा आधारभूत संरचना प्रबंधन के क्षेत्रों में श्री पाण्डेय ने व्यापक अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आपने इटली में ट्रैक रिकॉर्डिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया, सिंगापुर एवं मलेशिया में एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया, स्पेन में हाई-स्पीड ट्रेन परिचालन का प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा तुर्की एवं नॉर्वे में सुरंग निर्माण तकनीकों का प्रशिक्षण प्राप्त किया।

श्री पाण्डेय को आधारभूत संरचना के निर्माण तथा प्रबंधन एवं प्रशासन का व्यापक अनुभव प्राप्त है। आप अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच समान रूप से लोकप्रिय हैं और पूर्ण विश्वास है कि आपके गतिशील नेतृत्व में पश्चिम रेलवे नई उपलब्धियाँ हासिल करते हुए नई ऊँचाइयों को प्राप्त करेगी।

वडोदरा मंडल द्वारा 2.722 MWp क्षमता के सोलर संयंत्र की स्थापना से होगी प्रतिवर्ष 2.92 करोड़ की बचत

भारतीय रेल की हरित ऊर्जा नीति के अनुरूप पश्चिम रेलवे का वडोदरा मंडल सौर ऊर्जा के उपयोग को निरंतर बढ़ाते हुए ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके के मार्गदर्शन में वडोदरा मंडल के विद्युत विभाग द्वारा कुल 2.722 मेगावाट पीक (MWp) क्षमता के रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए गए। इन सौर संयंत्रों के परिणामस्वरूप मंडल को प्रतिवर्ष लगभग 2.92 करोड़ की बचत होगी, जो ऊर्जा लागत के अनुकूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (पावर) श्री प्रदीप मीणा ने बताया कि यह पहल पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इन संयंत्रों से प्रतिवर्ष लगभग 3.64 मिलियन यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा, जिससे ऊर्जा उपयोग की दक्षता में उल्लेखनीय सुधार होगा। साथ ही, मानक ग्रिड उत्सर्जन कारक के आधार पर इन संयंत्रों से लगभग 2632 टन CO उत्सर्जन में कमी आंकी जाएगी। 25 वर्षों की अनुमानित आयु अवधि में लगभग 65,800 टन CO उत्सर्जन से बचाव किया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग (पावर) मंडल में रेलवे स्टेशनों, सेवा भवनों एवं परिसरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है, जिससे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता में कमी लाई जा रही है। मंडल के विभिन्न प्रमुख स्थलों, जैसे वडोदरा स्टेशन परिसर, विद्युत लोको शेड तथा अंकलेश्वर स्टेशन सहित अन्य सेवा भवनों पर सौर संयंत्र स्थापित किए गए हैं। वडोदरा स्टेशन पर रनिंग रूम, टीटीई रेस्ट रूम, रिटायरिंग रूम, आरआरआई, लॉबी एवं कार्यालय भवनों की छतों का उपयोग करते हुए सौर ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित किया गया है। इसी प्रकार लोको शेड एवं अन्य परिसरों में भी उपलब्ध अवसंरचना का प्रभावी उपयोग किया गया है।

वडोदरा मंडल भविष्य में भी सौर ऊर्जा क्षमता के विस्तार एवं ऊर्जा दक्षता उपायों के क्रियान्वयन के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा उपयोग को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। सुनियोजित कार्यान्वयन एवं सतत निगरानी के साथ मंडल एक ऊर्जा-कुशल, किफायती एवं पर्यावरण-अनुकूल रेलवे प्रणाली के निर्माण की दिशा में अग्रसर है।